



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 152]

नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 27, 2003/आश्विन 5, 1925

No. 152]

NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 27, 2003/ASVINA 5, 1925

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

अधिसूचना

मुम्बई, 24 सितम्बर, 2003

सं. टीएमपी/38/2003-सीएचपीटी.—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण एतद्वारा चेन्नई पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड को उसके आयातित कच्चे तेल का प्रहस्तन करने के लिए बंदरगाह शुल्क में दी गई रियायत की अभिपुष्टि करने हेतु चेन्नई पत्तन न्यास से प्राप्त प्रस्ताव का, संलग्न आदेशानुसार, निपटान करता है।

अनुसूची

प्रकरण सं. टीएमपी/38/2003-सीएचपीटी

चेन्नई पत्तन न्यास (सीएचपीटी)

आवेदक

आदेश

(सितम्बर, 2003 के 10वें दिन पारित)

यह प्रकरण चेन्नई पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (सीपीसीएल) को, उसके आयातित कच्चे तेल का प्रहस्तन करने के लिए बंदरगाह शुल्क में दी गई रियायत की अभिपुष्टि करने हेतु चेन्नई पत्तन न्यास (सीएचपीटी) से प्राप्त प्रस्ताव से संबंधित है।

2. सीएचपीटी ने उल्लेख किया है कि उसने एन्नोर पत्तन लिमिटेड (ईपीएल) के शुरू होने के पश्चात 33.68 मी.ट. कार्गो प्रहस्तित किया है। ईपीएल को लौह अयस्क के प्रस्तावित स्थानांतरण के पश्चात, सीएचपीटी की कुल आवाजाही (कंटेनरों को छोड़कर) 180 लाख टन रह जाएगी। कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों का हिस्सा लगभग 42% है।

3. सीपीसीएल को बंदरगाह शुल्क में रियायत देने संबंधी अपने निर्णय के पक्ष में सीएचपीटी ने निम्नलिखित बातें कही हैं :-

- (i) ईपीएल के निर्माण के दौरान लिए गए निर्णयानुसार, पीओएल यातायात सीएचपीटी में ही रखा जाना था। अब, सीपीसीएल आयातित कच्चे तेल का प्रहस्तन करने के लिए एन्नोर पत्तन अथवा एसबीएम का उपयोग करने के विकल्पों पर विचार कर रहा है।

- (ii) सचिव (पोत परिवहन) ने 30 अक्तूबर, 2002 को ली गई अपनी बैठक में यह टिप्पणी की है कि तेल कार्गो का अन्य पत्तनों पर जाना पत्तनों के लिए संकट बने, इससे पूर्व सभी पत्तनों को पीओएल संबंधी प्रशुल्क की समीक्षा पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है।
- (iii) कच्चे तेल के प्रहस्तन की अखिसूचित बंदरगाह शुल्क दर 33/- रुपए प्रति मी.ट. है। सीएचपीटी ने वर्ष 2004-05 के लिए 9/- रुपए प्रति मी.ट. लागू का अनुमान लगाया है और सीपीसीएल ने 10/- रुपए प्रति मी.ट. का प्रस्ताव किया है। सीएचपीटी ने प्रारंभ में 27/- रुपए प्रति मी.ट. और सीपीसीएल की विस्तारण परियोजना के शुरू होने के पश्चात 10/- रुपए का प्रस्ताव किया है।
- (iv) जैसाकि कोई अन्य विकल्प नहीं है और चूंकि कच्चे तेल के प्रहस्तन की लागत सीपीसीएल की प्रस्तावित दर से कम ही है, इसलिए पत्तन को यह कार्गो बनाए रखना चाहिए।

4. कूटनीतिक कारणों और वित्तीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, सीएचपीटी ने सीपीसीएल के साथ औपचारिक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। गारंटीशुदा न्यूनतम आवाजाही के ब्योरे और एमओयू के अनुसार प्रभार निम्नानुसार है :-

- (i) सीपीसीएल सीएचपीटी को 1-4-2003 से सीएचपीटी में प्रहस्तित कच्चे तेल के लिए 27/- रुपए प्रति मी.ट. सुनिश्चित बंदरगाह शुल्क अदा करेगा।
- (ii) सीपीसीएल सीएचपीटी को 1-4-2005 से सीएचपीटी में प्रहस्तित कच्चे तेल के लिए 10/- रुपए प्रति मी.ट. बंदरगाह शुल्क अदा करेगा। आधार वर्ष 1984-85 से गैर-शारीरिक श्रमजीवी कर्मचारियों के अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में परिवर्तन के अनुसार इस बंदरगाह शुल्क में वार्षिक संशोधन किया जाता है। वर्ष 2005-06 से, 1 अप्रैल, 2005 से शुरू होने वाले तीन वर्षों के किसी प्रखंड में, यदि सीपीसीएल कुल 25.5 एमएमटीपीए कच्चा तेल आयात करने में नाकाम रहता है तो सीपीसीएल इस कमी के लिए तीन वर्षों के प्रखंड के अंतिम वर्ष में प्रचलित बंदरगाह शुल्क की दर पर सीएचपीटी को क्षतिपूर्ति करेगा।
- (iii) अंतरिम अवधि में अर्थात् सीपीसीएल की विस्तारण परियोजना के शुरू होने पर और 31 मार्च, 2005 तक, 6.5 एमएमटीपीए से अधिक आयातित बड़ी हुई मात्रा में कच्चे तेल पर सुनिश्चित बंदरगाह शुल्क 10/- रुपए प्रति मी.ट. हो जाएगा।
- (iv) सीपीसीएल की विस्तारण परियोजना के शुरू होने पर सीएचपीटी के माध्यम से पाइपलाइनों के जरिए सीपीसीएल द्वारा निर्यातित उत्पादों के लिए बंदरगाह शुल्क 904,895 मी.ट. की आधार मात्रा से अधिक बड़ी हुई मात्रा के संदर्भ में 10/- रुपए प्रति मी.ट. होगा। यह कच्चे तेल पर लागू वार्षिक संशोधन के अधीन होगा।

5. सीएचपीटी ने भी बंदरगाह शुल्क में वार्षिक संशोधन के परिकलन के लिए वर्ष के प्रारंभ और अंत में मूल्य सूचकांकों में वृद्धि की प्रतिशतता पर विचार करते हुए कार्यपद्धति निर्धारित की है।

6. सीएचपीटी ने आगे उल्लेख किया है कि चूंकि यह करार 30 वर्षों की अवधि के लिए किया गया है, इसलिए महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण अथवा अधिकार-क्षेत्र रखने वाले किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा भविष्य में किए जाने वाले प्रशुल्क संशोधन दरों और अनुबंध की शेष अवधि के लिए दरों में वृद्धि की कार्य-पद्धति को नहीं बदलेंगे।

7. इस परिप्रेक्ष्य में, सीएचपीटी ने इस प्राधिकरण से 1 अप्रैल, 2003 से विशेष दर लगाने और क्रमशः अनुच्छेद 4 और 5 में उल्लिखित कार्यपद्धति की अभिपुष्टि करने का अनुरोध किया है।

8. निर्धारित परामर्शी प्रक्रियानुसार, इस प्रस्ताव की प्रति संबंधित उपयोगकर्ताओं/पत्तन उपयोगकर्ताओं की प्रतिनिधि संस्थाओं को उनकी टिप्पणियों के लिए भेजी गई थी। इस प्रकरण को अंतिम रूप देने तक हमें उनकी लिखित टिप्पणियाँ प्राप्त नहीं हुई हैं।

9. पीओएल प्रहस्तन, भांडागारण और पत्तन-परिरक्षण सीएचपीटी में घाटे में चल रही अन्य सभी गतिविधियों को आर्थिक सहायता प्रदान करते हैं। सीएचपीटी से, सीपीसीएल को उसके द्वारा आयातित कच्चे तेल पर बंदरगाह शुल्क पर दी जाने वाली रियायत के कारण, घाटे में चल रही अन्य गतिविधि पर उसके वित्तीय प्रभाव दर्शाते हुए विश्लेषण प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था। सीएचपीटी से कोई प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

10. इस प्रकरण की संयुक्त सुनवाई 7 अगस्त, 2003 को चेन्नई में सीएचपीटी परिसर में की गई थी। इस संयुक्त सुनवाई में, सीएचपीटी अपने प्रस्ताव का अनुच्छेद 8 (जो विनिर्दिष्ट करता है कि टीएएमपी 30 वर्षों के लिए प्रस्तावित दरों में बदलाव नहीं करेगा) हटाने के लिए सहमत हो गया था। सीपीसीएल ने सीएचपीटी के प्रस्ताव पर अपनी सहमति दे दी है।

11. यहां यह उल्लेख करना उपयुक्त होगा कि चूंकि प्रस्तावित दर कच्चे तेल के वर्तमान अधिसूचित प्रशुल्क से ली गई है और उस दर पर पत्तन और सीपीसीएल दोनों की सहमति रही है, इसलिए संदर्भित प्रस्ताव पर इस प्राधिकरण का अंतिम निर्णय आने तक सीएचपीटी में प्रहस्तित कच्चे तेल पर पूर्व प्रभाव अर्थात् 1 अप्रैल, 2003 से 27/- रुपये प्रति मी.ट. की दर से रियायती बंदरगाह शुल्क लगाने हेतु, सीएचपीटी द्वारा किए गए अनुरोध के अनुसार, प्राधिकरण द्वारा तदर्थ अनुमोदन प्रदान किया गया था।

12. इस प्रकरण पर कार्यवाही के दौरान एकत्र की गई समग्र सूचना के संदर्भ से, निम्नलिखित स्थिति उभरती है :-

- (i) सीएचपीटी का यह प्रस्ताव सरकारी सोच का परिणाम है कि कच्चे तेल का कार्गो का अन्य पत्तनों का रुख करना संकट बनने से पूर्व सभी पत्तनों द्वारा पीओएल प्रशुल्क की समीक्षा करने की आवश्यकता है। सीएचपीटी तेल यातायात को बनाए रखने की विवशता से बंधा है। इसने स्पष्ट किया है कि सीपीसीएल अपने आयातित कच्चे तेल का प्रहस्तन करने के लिए अन्य पत्तनों/एसबीएम के बारे में विचार कर रहा था और सीएचपीटी सीपीसीएल के तेल यातायात से वंचित होना बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसने बंदरगाह शुल्क दर में रियायत देते हुए सीपीसीएल कार्गो को बनाए रखा है। इस दर पर पत्तन और सीपीसीएल दोनों परस्पर रूप से सहमत रहे हैं।
- (ii) पत्तन से, घाटे में चल रही गतिविधियों पर, आयातित कच्चे तेल पर बंदरगाह शुल्क में रियायत संबंधी प्रस्ताव से पड़ने वाले वित्तीय प्रभाव दर्शाने वाला विश्लेषण प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था। पीओएल प्रहस्तन गतिविधि घाटे में चल रही अन्य गतिविधियों को आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है। पत्तन ने कोई ऐसा विश्लेषण प्रस्तुत नहीं किया है। तथापि, यह सुस्पष्ट है कि प्रस्तावित कटौती की वजह से पीओएल गतिविधि से उपलब्ध अन्य गतिविधियों को मिलने वाली आर्थिक सहायता कम होगी।
- (iii) जैसाकि पहले उल्लेख किया गया है, कच्चे तेल के प्रहस्तन के दरमान में अनुमोदित दर उपलब्ध है। सीएचपीटी ने कारोबार को बनाए रखने के लिए अनुमोदित दर में छूट प्रस्तावित की है। यह इस पत्तन का वाणिज्यिक निर्णय है।
- (iv) यहां यह उल्लेख करना प्रासंगिक होगा कि भारत सरकार ने महापत्तन न्यास अधिनियम की धारा 111 के अधीन इस प्राधिकरण को दरमान को अधिकतम दरों के रूप में निर्धारित करने के लिए नीति निदेश जारी किया है ताकि महापत्तनों को, यदि वे ऐसा चाहें तो, कम की गई दरों पर वसूली करने का अधिकार मिल सके। सरकार की नीति को कार्यान्वित करने के लिए, इस प्राधिकरण ने हाल ही में 28 अगस्त, 2003 को आदेश पारित किया है और सभी महापत्तन न्यासों को अपने-अपने दरमान में यह सामान्य सशर्तता शामिल करने का निदेश देते हुए भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया है कि दरमान में निर्धारित दरें अधिकतम दरें हैं; इसी प्रकार, कटौतियां और छूट निम्नतम हैं। पत्तन न्यास, यदि वह ऐसा चाहे तो, निम्नतर दरें वसूल कर सकता है और/अथवा अधिक कटौतियां और छूट प्रदान कर सकता है।

चूंकि दरमान में शामिल किया गया यह संशोधन पत्तन को अपने वाणिज्यिक निर्णय के आधार पर कम की गई दरों पर वसूली करने का आवश्यक अधिकार प्रदान करता है, इसलिए इस प्राधिकरण को सीपीसीएल के कच्चे तेल के आयात की बंदरगाह शुल्क दरों में विशिष्ट कटौतियां करने और वार्षिक संशोधन की कार्यपद्धति पर विचार करने और उन्हें अनुमोदित करने की आवश्यकता नहीं है।

- (v) सीएचपीटी ने अपने पूर्व रुख को बदल दिया है कि यह प्राधिकरण उसके द्वारा प्रस्तावित 30 वर्षों के लिए दरों में संशोधन नहीं करेगा और अपने प्रस्ताव के प्रासंगिक अनुच्छेद को हटाने का अनुरोध किया है। पत्तन और उपयोगकर्ता के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) इस प्राधिकरण को दी गई सांविधिक शक्तियों का अधिक्रमण नहीं कर सकता। जैसाकि दरों के प्रचालन में पत्तन को अधिकार दिया जा रहा है, सामान्यतः, इस प्राधिकरण को समझौता ज्ञापन के प्रचालन को लेकर हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं होगी। तदपि, इस प्रकरण में प्रकट होने वाली असाधारण स्थिति, यदि कोई हो, में वर्तमान निर्णय से हटने की आवश्यकता होगी तो यह प्राधिकरण समझौता ज्ञापन के प्रचालन के दौरान भी संशोधनात्मक कार्यवाहियाँ करेगा।
- (vi) जैसाकि पहले उल्लेख किया गया है, सीएचपीटी में प्रहस्तित सीपीसीएल के कच्चे तेल पर पूर्वव्यापी प्रभाव अर्थात् 1 अप्रैल, 2003 से 27/- रुपये प्रति मी.ट. रियायती बंदरगाह शुल्क दर वसूल करने के लिए सीएचपीटी का अंतिम निर्णय आने तक तदर्थ अनुमोदन प्रदान किया गया है। पहले प्रदान किए गए तदर्थ अनुमोदन की अभिपुष्टि की जाती है। यह उल्लेखनीय है कि इस प्राधिकरण द्वारा 'अधिकतम दरों' के संबंध में किया गया सामान्य निर्धारण 2 सितम्बर, 2003 से प्रभावी हो गया है। इस प्रकरण में सीएचपीटी 1 अप्रैल, 2003 से वर्तमान दर 33/- रुपये प्रति मी.ट. को 27/- रुपये प्रति मी.ट. करना चाहता था। सीएचपीटी द्वारा समझौता ज्ञापन के उपबंधों को कार्यान्वित करने का अधिकार देने के लिए, प्रदान किए गए तदर्थ अनुमोदन द्वारा बंदरगाह शुल्क दर में की गई कटौती 1 अप्रैल, 2003 से 1 सितम्बर, 2003

अवधि के लिए वैध रहेगी, उसके पश्चात पूर्वस्थिति प्रत्यावर्तित होगी। उपर्युक्त अनुच्छेद (iv) में स्पष्ट किया गया है कि प्रस्तुत किए गए संशोधन के मद्देनजर सीएचपीटी को 2 सितम्बर, 2003 से अधिसूचित दर में कमी करने की सीमा पर निर्णय लेने का अधिकार है।

13. परिणामस्वरूप, उपर्युक्त कारणों से और समग्र विचार-विमर्श के आधार पर, यह प्राधिकरण सीएचपीटी के प्रस्ताव को अनावश्यक मानकर निपटान करता है।

अ. ल. बोंगिरवार, अध्यक्ष

[सं. विज्ञापन/III/IV/143/03-असाधारण]

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

NOTIFICATION

Mumbai, the 24th September, 2003

No. TAMP/38/2003-CHPT.— In exercise of the powers conferred under Section 48 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Tariff Authority for Major Ports hereby disposes of the proposal of the Chennai Port Trust for ratification of concession in wharfage granted to the Chennai Petroleum Corporation Limited for handling of their import crude oil as in the Order appended hereto.

SCHEDULE

Case No. TAMP/38/2003-CHPT

The Chennai Port Trust

Applicant

ORDER

(Passed on this 10th day of September 2003)

This case relates to a proposal received from the Chennai Port Trust (CHPT) for ratification of concession in wharfage granted to the Chennai Petroleum Corporation Limited (CPCL) for handling of their Import Crude Oil.

2. The CHPT has stated that it has handled 33.68 MT of cargo after commissioning of Ennore Port Limited (EPL). After the proposed shifting of Iron Ore to the EPL, the CHPT will have a total throughput (excluding containers) of 18 million tonnes. The share of crude and petroleum products is around 42%.

3. The CHPT has made the following points in favour of its decision to offer concessional wharfage to the CPCL:

- (i). POL traffic was to be retained at CHPT as per the decision taken during the formation of the EPL. Now, the CPCL is considering options for utilizing Ennore Port or SBM for the handling of crude imports.
- (ii). The Secretary (Shipping) has observed in the meeting taken by him on 30 October 2002 that the review of tariff by all the ports relating to POL needs urgent attention before the diversion of oil cargo becomes a threat to the ports.
- (iii). The notified wharfage rate for handling crude oil is Rs.33/- PMT. The CHPT has estimated the cost per MT at Rs.9/- for the year 2004-05 and the CPCL has offered Rs.10/- PMT. The CHPT has offered Rs.27/- PMT initially and Rs.10/- after commissioning of CPCL's expansion project.

- (iv). As there is no other alternative and since the cost of handling crude oil is less than the offered rate of the CPCL, the port should retain the cargo.

4. In consideration of the strategic reasons and financial requirement, the CHPT has entered into a formal Memorandum of Understanding (MoU) with the CPCL. The details of minimum guaranteed throughput and the charges as per the MOU are as under:

- (i). The CPCL shall pay CHPT a firm wharfage of Rs.27/- per MT of crude handled at CHPT from 1.4.2003.
- (ii). The CPCL shall pay CHPT a wharfage of Rs.10/- per MT of crude handled at CHPT from 1.4.2005. The wharfage is subject to annual revision as per the change in All India Consumer Price Index Number for urban non-manual employees with base year 1984-85. From 2005-06, in any block of three years commencing from 1 April 2005, if the CPCL fails to import a total of 25.5 MMTPA of crude oil, the CPCL shall compensate the CHPT for the shortfall, at a wharfage rate prevailing in the terminal year of the three year block.
- (iii). In the interim period i.e., on the commissioning of the CPCL's expansion project and upto 31 March 2005, the firm wharfage on the incremental crude imported beyond 6.5 MMTPA is to be Rs.10/- per MT.
- (iv). On commissioning of the CPCL's expansion project, the wharfage charges for the products exported by the CPCL through the CHPT through pipelines, with reference to the incremental quantity over the base quantity of 904,895 MT will be at Rs.10/- per MT. This will be subject to annual revision as applicable for crude oil.

5. The CHPT has also prescribed a methodology for calculation of annual revision of wharfage considering the percentage of increase in the Price Indices at the beginning and at the end of the year.

6. The CHPT has further stated that since the agreement is entered into for a period of 30 years, tariff revisions which will be effected by TAMP or any other Authority who may have the jurisdiction shall not change the rates and method of escalation of the same during the pendency of the agreement.

7. In this backdrop, the CHPT has requested the Authority to ratify the charging of special rate with effect from 1 April 2003 and the methodology mentioned in paragraph 4 and 5 respectively.

8. In accordance with the consultative procedure prescribed, a copy of the proposal was forwarded to concerned users / representative bodies of port users for comments. We have not received their written comments till finalisation of this case.

9. POL handling, warehousing and port conservancy subsidise all other activities which are in deficit in CHPT. The CHPT was requested to furnish an analysis showing the financial implication on other activities which are in deficit due to the concessional wharfage to be granted on crude oil import by the CPCL. No response has been received from the CHPT.

10. A joint hearing in this case was held on 7 August 2003 at the CHPT premises in Chennai. At the joint hearing, the CHPT agreed to delete paragraph 8 of its proposal (Stipulating that TAMP shall not alter the proposed rates for 30 years). The CPCL conveyed its agreement with the proposal of the CHPT.

11. It is pertinent to mention here that since the proposed rate has been derived from the existing notified tariff for crude oil and that the rate has been mutually agreed upon by the port and the CPCL, adhoc approval was accorded, as requested by the CHPT, to levy the concessional wharfage rate of Rs.27/- per MT retrospectively with effect from 1 April 2003 on crude oil handled at the CHPT subject to the final decision of this Authority on the proposal in reference.

12. With reference to the totality of information collected during the processing of this case, the following position emerges:

- (i). The proposal of the CHPT is the outcome of the Government thinking that all ports need to review the POL tariff before its diversion becomes a threat to the ports. The CHPT is under compulsion to retain the oil traffic. It has explained that the CPCL was considering other port / SBM to handle its crude imports and the CHPT cannot afford to lose the oil traffic of the CPCL. It has retained the CPCL cargo by offering concession in wharfage rate. The rate has been mutually agreed upon by the port and the CPCL.
- (ii). The port was asked to furnish an analysis showing the financial implication on other activities which are in deficit due to the concessional wharfage proposal on crude oil import. The POL handling activity is subsidising other activities which are in deficit. The port has not furnished any such analysis. Nevertheless, it is obvious that cross-subsidy available from POL activity will reduce because of the proposed reduction.
- (iii). As has been mentioned earlier, there is an approved rate available in the Scale of Rates for handling of crude oil. The CHPT has offered concession in the approved rate to retain business. This is a commercial decision of the port.
- (iv). It may be relevant to mention that the Government of India has issued a policy direction to this Authority under Section 111 of the MPT Act to fix the Scale of Rates as ceiling rates so that the major ports have the flexibility to charge at reduced rates, if they so desire. In order to implement the policy of the Government, this Authority has recently passed an Order on 28 August 2003 and notified it in the Gazette of India directing all the major port trusts to include a general conditionality in their Scale of Rates stating that the rates prescribed in the Scale of Rates are ceiling levels; likewise, rebates and discounts are floor levels. The Port Trust may, if it so desires, charge lower rates and / or allow higher rebates and discounts.

Since this amendment introduced in the Scale of Rates provides necessary flexibility to the port to charge reduced rates based on its commercial judgement, it is not necessary for this Authority to go into the specific reductions in wharfage rates for Import crude oil of CPCL and the methodology for annual revision and approve them.

- (v). The CHPT has changed its earlier stand that this Authority shall not alter its proposed rates for 30 years and requested to delete the relevant paragraph of its proposal. The MOU between the port and the user cannot supersede the statutory powers vested in the Authority. As flexibility is being given to the port in operation of the rates, normally, there may not be a need for this Authority to interfere with the operation of the MOU. Still, in the event of extraordinary position, if any, emerging in this case warranting a deviation from the present stand, this Authority will take corrective actions even during the currency of the MOU.

- (vi). As has been brought out earlier, adhoc approval to levy the concessional wharfage rate of Rs 27/- PMT retrospectively with effect from 1 April 2003 on the crude oil of CPCL handled at the CHPT has been granted subject to the final decision of this Authority. The adhoc approval accorded earlier is ratified. It is noteworthy that the general prescription made by this Authority about 'ceiling rates' has come into effect from 2 Sept 2003. The CHPT in this case wanted to reduce the existing rate of Rs 33/- PMT to Rs 27/- PMT w.e.f. 1 April 2003. To enable the CHPT to implement the provisions of the MOU, the reduction in wharfage rate made by the adhoc approval accorded will remain valid for the period from 1 April 2003 to 1 Sept 2003 whereafter the status quo ante will revert. The CHPT has the flexibility to decide the extent of reduction in the notified rate to be allowed w.e.f. 2 Sept 2003 in view of the amendment introduced as explained in paragraph (iv) above.

13. In the result, and for the reasons given above, and based on a collective application of mind, this Authority disposes of the proposal of the CHPT as superfluous.

A. L. BONGIRWAR, Chairman
[No. ADVT/III/IV/143/03-Exty.]